



जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Did Jahangirnama Fall Prey To His Son's Dislike Of Him?

A painting was certainly intended for a copy of the Jahangirnama, but ended up in an album created for his son when he became emperor, showing Jahangir's close interest in nature

Protect Your Pup The Essential Vaccination Checklist for Dogs

सचिन पायलट होंगे कांग्रेस का नया ओबीसी चेहरा

राहुल गांधी ने यह सोचा समझा निर्णय लिया, जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद। इस निर्णय से बैकवर्ड, दलित व आदिवासी देश की राजनीति में अब पूरी तरह से सैंटर स्टेज पर आ गये हैं

**-रेणु मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी का नया ओबीसी चेहरा हैं। राहुल गांधी ने बहुत सोच-विचार कर उन्हें, खासतौर से जातिगत जनगणना के संदर्भ में, पार्टी के नये ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि जातिगत सर्वे ने पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र में पहुँचा दिया है।
आज शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की मीटिंग के बाद, सचिन पायलट और भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस के लिये उतारा गया। ये दोनों ही ओबीसी हैं। लेकिन चूँकि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिये वे ईडी की नज़र में हैं तथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। बघेल का समय गुज़र चुका है।
सचिन पायलट युवा और करिश्माई नेता हैं। वे स्वच्छ छवि के मालिक हैं तथा युवा एवं महिलाएं उनकी जबरदस्त प्रशंसक एवं समर्थक हैं। उनकी लोकप्रियता केवल राजस्थान में ही नहीं,

- सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक के बाद, शाम को सचिन पायलट व भूपेश बघेल को प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करने के लिये उतारा कांग्रेस हाईकमान ने।
- दोनों, नेता ओबीसी हैं। बघेल हालांकि वजनी हैं, क्योंकि, मु.मंत्री रह चुके हैं, परन्तु उन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है तथा भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
- अतः बघेल बीता हुआ, “पास्ट” (इतिहास) हैं। पर, पायलट युवा हैं, करिश्माई हैं तथा साफ व स्वच्छ छवि के नेता हैं, जिनकी युवाओं में, महिलाओं में, अच्छी लोकप्रियता है, केवल राजस्थान में ही नहीं, पर, उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी।
- राहुल गांधी लगातार “जातिगत जनगणना” की बात कर रहे थे तथा ओबीसी, दलित व आदिवासी को पुनः कांग्रेस में लाने के लिये जातिगत नेताओं (कास्ट लीडर्स) को प्रोजैक्ट करने की जरूरत को पहचान रहे हैं।

अपितु पूरे उत्तर भारत में है। अगर कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिये जोर लगाया होता, तो वे किसी भी पार्टी के प्रथम गुर्जर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आये होते और कांग्रेस

कार्यान्वित करना बिल्कुल भिन्न चीज है। चूँकि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के महत्व और आवश्यकता के बारे में, तथा ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को कांग्रेस में वापस लाने की जरूरत के बारे में निरन्तर बात करते आ रहे हैं, इसलिये उन्होंने पिछड़ी जातियों के नेताओं को प्रोजेक्ट करना शुरु कर दिया है। अपेक्षानुरूप, सीडब्ल्यूसी मीटिंग मूलतः दो बिन्दुओं पर केंद्रित थी: पहलगाम हमला, जिसके विषय में एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री से कहा गया कि वे पाकिस्तान तथा उसके द्वारा पोषित आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। दूसरा बिन्दु जातिगत जनगणना थी, जिसके बारे में सरकार ने जो घोषणा की है, उससे कहीं बहुत ज्यादा कांग्रेस चाहती है।
कांग्रेस को आशंका है कि मोदी सरकार के अन्य जुमलों की तरह, जातिगत जनगणना भी कहीं एक जुमला बनकर न रह जाये। सीडब्ल्यूसी ने जो देकर कहा कि जातिगत सर्वे सही रूप में कार्यान्वित हो, जिससे यह सामाजिक सशक्तीकरण एवं परिवर्तन का एक प्रभावी उपाय बन सके।

महेश जोशी को 8 से 11 मई की अंतरिम जमानत मिली

जयपुर, 2 मई। ईडी मामलों की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के करीब 900 करोड़ रुपए घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को, उनकी पत्नी के निधन के चलते, 8 से 11 मई तक अंतरिम जमानत का लाभ दिया है। जोशी को अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 11 मई को सुबह 8 बजे जेल में सरेंडर करना होगा। इससे पहले ईडी कोर्ट ने जोशी को गत 28 अप्रैल को पत्नी के अंतिम क्रिया- कर्म व धार्मिक रिवाजों के निर्वाह के लिए 4 दिन की अंतरिम

- महेश जोशी के अधिवक्ता ने पत्नी के निधन के संबंध में रीति-रिवाजों के लिये अंतरिम जमानत 9 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

जमानत दी थी। इस अंतरिम जमानत अवधि को बढ़ाने के लिए जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला शुक्रवार पर रखा था। वहीं, अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार शाम को जोशी ने जेल में सरेंडर कर दिया था।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता दीपक चौहान ने कहा कि महेश जोशी की उनकी पत्नी के निधन के बाद के रीति रिवाजों में हिस्सा लेना है। वे 71 साल के हैं और पत्नी के निधन के बाद (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गिरते पड़ते, किसी भी तरह शशि थरुर पहुँच ही गये, एयरपोर्ट प्र.मंत्री को “रिसीव” करने

इससे प्र.मंत्री मोदी को मौका मिल गया, कांग्रेस पर कटाक्ष करने का कि थरुर के इस कठिन प्रयास से कई नेताओं की नींद उड़ जायेगी

**-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। तिरुवन्तपुरम लोकसभा सांसद शशि थरुर, जो हमेशा घूमते रहते है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जो गुरुवार रात केरल की राजधानी पहुँचे थे, के आगमन पर स्वागत के लिये ठीक समय पर पहुँच ही गये थे और इससे प्रधानमंत्री को थरुर की कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करने का अवसर मिल गया।

मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुये कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरुर की यहाँ विज़िजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर मौजूदगी से बहुत से लोगों की “रातों की नींद उड़ गई होगी।”

थरुर की वहाँ मौजूदगी पर मोदी की सीधी टिप्पणी ऐसे समय हुई है, तिरुवन्तपुरम के कांग्रेस सांसद (थरुर) पर उन्हीं की पार्टी के उनके साथी यह आरोप लगा रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले पर थरुर भाजपा के प्रति नरम रख अपना रहे हैं।

थरुर ने सोशल मीडिया पर बताया कि वे किस तरह एयरपोर्ट पहुँचे। उन्होंने

- मोदी का कटाक्ष इसलिए मायने रखता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता, आजकल थरुर पर आरोप लगा रहे हैं कि थरुर पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद से भाजपा के प्रति अधिक नरम हो गये हैं, उतने आक्रामक नहीं रहे।

“एक्स” पर लिखा, “दिल्ली एयरपोर्ट पर विलम्ब हो जाने के बावजूद, मेरे लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर, उनके स्वागत के लिये मैं किसी तरह तिरुवन्तपुरम समय पर पहुँच ही गया। विज़िन्जम पोर्ट, जिस प्रोजैक्ट से शुरु से ही जुड़े होने का मुझे गर्व है, को उनके द्वारा विधिवत रूप से लोकार्पित किये जाने की मुझे उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा थी।”

प्रधानमंत्री मोदी की 2025 में यह पहली केरल यात्रा है और यहाँ एक बहुत बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट को लोकार्पित करने आये हैं, जो केरल ही नहीं, पूरे देश के स्वरूप को बदल देगा। शशि थरुर 2009 से निरन्तर तिरुवन्तपुरम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और

विज़िंजम तो उनके मन में बसता है। केरल की राजधानी की अभूतपूर्व रूप से सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, प्रधानमंत्री तिरुवन्तपुरम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। विज़िन्जम इंटरनेशनल डीपवॉटर मल्टीपरवज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करने केरल की राजधानी में आये। यह 8900 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुआ है।

यह देश का प्रथम कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में, “विकसित भारत” के स्वप्न के हिस्से के रूप में, क्रांतिकारी तरक्की का प्रतिनिधित्व करता है।

सामरिक महत्व वाले विज़िन्जम पोर्ट की पहचान अत्यधिक प्राथमिकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असुरक्षित होटलों के संचालन पर रोक लगायें

राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर होटल अग्निकांड पर दिशा निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अजमेर के होटल में हुए अग्निकांड के बाद ऐसे असुरक्षित होटलों को बंद करने की मंशा जताई है। आयोग ने कहा कि अजमेर में रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जिला प्रशासन और नगर निगम सभी सरायों और होटलों की सूची बनाकर, उन्हें असुरक्षित पाए जाने पर, उनके संचालन पर रोक लगाए। इसके साथ ही, इन होटलों में फायर एनओसी की अनिवार्यता को लागू करें, ताकि यहां ठहरने वालों को इस अग्निकांड जैसी जानलेवा घटना न हो। वहीं, आयोग ने अजमेर कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त को कहा है कि शहर की सभी होटलों की सूची बनाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को कन्फर्म कर

- आयोग ने अजमेर कलैक्टर, एसपी तथा निगम आयुक्त को अजमेर के होटलों की सूची बनाकर सुरक्षा व्यवस्था की कन्फर्म रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इसकी रिपोर्ट आयोग में पेश की जाये और अग्निकांड में पीड़ितों को क्षतिपूर्ति राशि देना सुनिश्चित किया जाये। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश मामले में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर दिए।

आयोग ने कहा कि अग्निकांड में जले होटल के मालिक ने स्थानीय प्रशासन से बिना फायर एनओसी लिए होटल संचालित की, जिसके चलते आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आग की लपटें देखकर होटल कर्मचारी भाग गए और

एक महिला को अपने बच्चे को बचाने के लिए होटल से नीचे फेंकना पड़ा। आयोग ने कहा कि शहर के कई आवासीय भवनों को होटलों में तब्दील किया जा चुका है और विभागों की स्वीकृति और एनओसी के बिना इनका संचालन किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से इस आवश्यक पहलू को नजरअंदाज किया गया है, जिससे दरगाह के आसपास अग्निकांड होने पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने और बचाव कार्य में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के टेंडरों की जाँच के लिये आठ सप्ताह का समय

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से बीते पांच साल में दिए पांच सौ टेंडरों में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर जाँच एजेंसी को आठ सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका

- विभाग के पाँच साल के पाँच सौ टेंडरों की जाँच के लिये गठित एसआईटी ने जाँच के लिये हाई कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा।

पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अदालत में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर कहा कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हिमांशी तुम एक “परफैक्ट” फौजी वाइफ हो’

ले. विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का भारतीय नौ सेना के तेरहवें एडमिरल की पत्नी ललिता रामदास ने अभिनंदन किया

**-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 2 मई। भारतीय नौ सेना के तेरहवें एडमिरल स्व. रामदास की पत्नी ललिता रामदास, जो एक शिक्षाविद् हैं, ने हिमांशी नरवाल की प्रशंसा की और कहा कि वे सही मायने में एक “फौजी की पत्नी” (परफैक्ट फौजी वाइफ) हैं, हिमांशी के पति लैफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगाम हमले में शहीद हो गए थे।

गुरुवार को विनय नरवाल का 27 वां जन्मदिन था। हिमांशी ने अपने दुख और पीड़ा को दर्किनार रखकर शांति और सद्भावना की अपील कर गरिमा और परिपक्वता का परिचय दिया है। जिसका सोशल मीडिया पर कई दक्षिण पंथियों ने विरोध किया।

हिमांशी ने कहा, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाया जाए। लेकिन हम न्याय

- जैसा कि विदित ही है, ले. विनय नरवाल गत 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हो गये थे और हिमांशी शादी के दस दिन बाद ही विधवा हो गई थी।

- गत गुरुवार को ले. नरवाल का 27वां जन्म दिन होता। उस दिन हिमांशी ने अपील की थी कि जो लोग ले. नरवाल के मौत का कारण बने, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये। पर, मैं नहीं चाहती कि हमें सभी मुसलमानों व कश्मीरियों पर गुस्सा निकालना चाहिये और उन्हें गालियाँ देनी चाहिये।

चाहते हैं। जिन लोगों ने विनय की हत्या की, उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। हिमांशी ने यह बात हरियाणा के करनाल में एक रक्तदान शिविर में पत्रकारों से बात करते हुए कही।

ललिता रामदास ने एक नोट में लिखा कि हिमांशी, आप सही मायने में फौजी की पत्नी हैं, सेना, संविधान और

धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुकूल हैं। हिमांशी, जो अपनी शादी के 6 दिन बाद ही विधवा हो गई थीं, को ललिता रामदास ने यह नोट लिखा। जाने-माने पत्रकार व लेखक परन्जॉय गुहा ठाकुरता ने यह पत्र सोशल मीडिया पर डाला है।

हिमांशी और विनय हनीमून के

लिए कश्मीर गए थे, क्योंकि यूरोप का वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी।

ललिता रामदास ने लिखा, “नौसेना अधिकारी की संभवतया सबसे उग्रदराज बेटी व पत्नी, जो आज भी जीवित है, की तरफ से नौसैनिक अधिकारियों की पत्नियों की जमात में शामिल सबसे युवा सदस्य को व्यक्तिगत टिप्पू है।” ज्ञातव्य है कि ललिता के पिता भी नेवी में एडमिरल थे।

ललिता ने लिखा, “मुझे आप पर बहुत गर्व है, और मैं प्रैस से कहे गए आपके शब्दों की क्लिप बार-बार देखती हूँ। बाइस तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की जघन्य हत्या के बाद, जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशान बनाने और नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो आपकी असाधारण शक्ति, धैर्य और दृढ़ विश्वास वाकई उल्लेखनीय है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नैशनल हैरल्ड केस, सोनिया व राहुल को कोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली, 02 मई। राष्ट्रीय राजधानी में एक विशेष अदालत ने नेशनल हैरल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। इससे पहले इसी माह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ

- नैशनल हैरल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्देश पर न्ययाधीश ने ये नोटिस जारी ? किए हैं।

अदालत में कार्यवाई के लिए नयी शिकायत दायर की थी। इसमें संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाये गये हैं।

मामले की सुनवाई कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम) ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किये। यह मामला (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर, 2 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाए जाने से जुड़े मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा है कि वे चुनाव कार्यक्रम सहित बताए

- हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 फरवरी तथा 25 मार्च 2025 के निर्देशों की पालना करने के लिये भी कहा।

कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। वहीं, राज्य सरकार को इस संबंध में 4 फरवरी 2025 व 25 मार्च 2025 को दिए गए निर्देशों की पालना के लिए कहा है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जस्टिस चन्द्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गिराज सिंह देवदा व अन्य की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 30 मई को तय की है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

रेटपेयर्स की सक्रिय भागीदारी से ही अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी

भले ही आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो व जीडीपी रैंकिंग में इस साल हम विश्व की तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में हैं पर अर्थ व्यवस्था के तेजी से विकास के लिए रेटपेयर्स की भागीदारी बढ़ाने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। फ्रीबीज के जमाने में केन्द्रीय वित्त सचिव अजय सेठ द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रेटपेयर्स को प्रोत्साहित करना जरूरी बताया है। दरअसल एक और राजनीतिक दलों द्वारा ऐन केन प्रकारेण सत्ता के स्वाद चखने की चाह पूरी करने के लिए लोकलुभावन फ्रीबीज सुविधाओं की घोषणाएं दर घोषणाएं की जा रही है तो दूसरी और देश को 2025 में जीडीपी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की चुनौती सामने हैं। अर्थव्यवस्था का सीधा-सीधा गणित यह है कि एक तो करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कर के रुप में सीधे-सीधे आय सरकार को प्राप्त होती है तो दूसरी और सरकार अपनी विकास योजनाओं को अमलीजामा पहुंचाने के लिए उधारी से काम चलाने वाली स्थिति होती है जिसे हम बजट प्रस्तावों में उधारी के रुप में देखते हैं तो तीसरा प्रमुख स्रोत रेटपेयर्स होते हैं। देश का सेविंग पूल इन्हीं से बनता है। अब जहां तक आयकर का प्रश्न है तो आधार और पेनकार्ड के चलते अब आयकर के दायरें से तो कोई बच भी नहीं सकता। खासतौर से नौकरीपेशा या निश्चित प्रपाग पाने वालों का तो आयकर सीधे-सीधे और बिना किसी छीजत के सरकार को प्राप्त हो ही जाता है। इसमें किसी तरह की चोरी की संभावना भी लगभग ना ही है। लगभग यही स्थिति जीएसटी के बाद देखने को मिल रही है और साल दर साल जीएसटी संग्रहण में बढोतरी देखने को मिल रही है।

दरअसल जब स्थानीय स्वशासन को परिकल्पना की गई थी तो उसके साथ यह भी था एक समय आते-आते यह संस्थाएं अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर हो जाएगी और इन संस्थाओं को सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर एक और यह तो सपना ही बनकर रह गया दूसरी और राजनीतिक दलों ने फ्रीबीज का ऐसा चलन चलाया कि रेटपेयर्स की भूमिका कम से कम होती जा रही है। दरअसल रेटपेयर्स का प्रयोग सबसे पहले 1845 में माना जाता है। रेटपेयर्स की

रेटपेयर्स से सीधा सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरें में आती हैं। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरें में प्रमुखता से ला रही हैं। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थ व्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

पर फ्रीबीज के दायरें में प्रमुखता से ला रही है। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थ व्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

लोकतंत्र में समान अवसर और आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए अनुदानित योजनाओं का संचालन सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। संवेदनशील और लोकहितकारी सरकार के लिए यह आवश्यक भी हो जाता है। पर इसका मायना यह नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जो राशि कर या अन्य रुप में प्राप्त की जाती है वह नहीं मिले और उसका भार भी ईमानदार कर दाताओं पर पड़े तो यह किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता है। फिर सरकार को सक्षम और कम सक्षम में कहीं ना कहीं अंतर करके ही चलना ही होगा। केन्द्रीय वित्त सचिव की मंशा कहीं ना कहीं यही होगी कि फ्रीबीज के कारण जो रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी दिन-प्रतिदिन कम हो रही है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सहायता दी जाए पर इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि मुख्यधारा से वंचित के नाम पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोगों या परिवारों को भी यह सुविधाएं दी जाएं। इससे होता यह है कि जो आम करदाता है वह तो अपने आपको उगा मरसूस करता ही है वहीं कहीं ना कहीं समाज में गेप भी बढ़ता है। इसके अलावा आर्थिक विकास में जो जनभागीदारी होनी चाहिए वह भी बाधित होती है। ऐसे में फ्रीबीज की राजनीति के बीच रेटपेयर्स की भागदारी को भी बढ़ाना ही होगा जिससे अर्थव्यवस्था का मल्टिपल विकास संभव हो सके। आज के लाभार्थियों को भी अर्थ व्यवस्था के व्यापक हित में समझना होगा।

–अमितिश सम्पादक, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, (वरिष्ठ लेखक)



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शनिवार 3 मई, 2025

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठि तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, पुनर्वसु नक्षत्र दिन 12:34 तक, शूल योग रात्रि 1:41 तक, तैत्तिल करण प्रातः 7:52 तक, चन्द्रमा प्रतः 6:37 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रविवोग दिन 12:34 तक है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 7:52 से 2:02 तक है। आज गंगा सप्तमी और पूजन, गंगोत्पत्ति और चन्दन छठ है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:29 से 9:07 तक, चर 12:24 से 2:02 तक, लाभ अमृत 2:02 से 5:18 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:51, सूर्यास्त 6:56

 मेघ घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 सिंह घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।	 धनु चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नई है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।
 वृष परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	 कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	 मकर परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में चल रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।
 मिथुन आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 तुला व्यावसायिक कार्यों को प्रगतिमान करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 कुंभ स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 कर्क व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।	 वृश्चिक नवीन कार्यों के संबंध में सरकाराव्यक्त आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	 मीन व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

संपादकीय

तकनीकी युग में चुनाव आयोग में बड़े बदलावों और नवाचार की आवश्यकता है



सुनील दत्त गोयल

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान प्रदत्त है। लेकिन जब यह अधिकार गैर-नागरिकों यानी अवैध रूप से देश में दाखिल हुए घुसपैठियों को मिल जाए, तो यह लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। आज भारत इस गंभीर चुनौती से जूझ रहा है-विशेषकर सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में यह समस्या अधिक विकराल रूप ले चुकी है।

चुनाव आयोग को आधुनिकरण की जरूरत है। पिछले 15 वर्षों में चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद जरूरी सुधारों और बदलावों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया है। हर चुनाव-चाहे लोकसभा हो या विधानसभा या ग्राम सभा-के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट होती है। यह समझ से परे है कि अब तक एक सामान्य वोटर लिस्ट क्यों नहीं बनाई गई है जो सभी स्तरों के चुनावों के लिए मान्य हो। मेरा पहला सुझाव यही है कि एक सामान्य जनरल वोटर लिस्ट बनाई जाए। दूसरा अहम मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटिजन्स) को घर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के आधार पर वोटिंग की सुविधा देने का ट्रायल शुरू किया है। यह सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर देश से बाहर रहने वाले नागरिकों, दूसरे राज्यों में रह रहे कामकाजी लोगों या छात्र-छात्राओं को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती? उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक या पोस्टल माध्यम से वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए।

मैंने स्वयं लासभग एक साल पहले अपना वोटर आईडी ऑनलाइन अपडेट किया था, लेकिन आज तक वह मुझे नहीं मिला। इससे यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? इसे समय से आगे की सोच अपनीानी होगी और तकनीकी रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा।

चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों की सीमाएं : एक और बड़ा मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनाती तो कर देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट (क्लेक्टर) और एसपी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। यह सही है कि आचार संहिता के समय वे आयोग के अंतर्गत होते हैं, लेकिन उसके बाद पुनः राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि सुरक्षा बलों की तैनाती चुनाव प्रक्रिया में और गहराई तक की जाए, खासकर पोलिंग बूथ के अंदर।

अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जहां पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार के कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करते दिखते हैं। वोट किसے देना है, यह पूछते हैं और कई बार खुद वोट डाल देते हैं। यह अपमान और नया 'बूथ कैम्पेरिंग' का तरीका है। इसे रोकने के लिए जरूरी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल पोलिंग बूथ के अंदर तैनात हों और प्रत्येक वोटिंग प्रक्रिया पर निगरानी रखें। यहाँ हमारा यह सुझाव है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनाती कहाँ और किस स्थान पर और कितनी होगी, यह भी चुनाव आयोग स्वयं अपने स्तर पर फैसला करें। तभी हम एक पारदर्शी और सुशुद्ध चुनाव प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं।

आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो : आज हमारे पास ई-आधार, मोबाइल, फेस आईडी और तमाम डिजिटल साधन मौजूद हैं। ऐसे में डाक द्वारा वोट भेजने की पुरानी प्रणाली को खत्म कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को विकसित करना चाहिए, ताकि जो लोग अपने गृह जनपद से बाहर हैं, वे भी आसानी से वोट डाल सकें। जैसे चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारी तथा सीमा पर लगे हुए सैन्य अधिकारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों में वे सभी अधिकारी जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर होते हैं, वे पोस्टल बलेट का उपयोग करते हैं। वैसे ही आम नागरिकों को भी दो दिन पहले वोट डालने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलनी चाहिए। यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है।

स्थानीय कारकों को समझे चुनाव आयोग : चुनाव आयोग को चाहिए कि वह अपने जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह जानकारी अवश्य प्राप्त करे कि उनके जिलों में मतदान के दिन या उससे एक-दो दिन पहले अथवा बाद में कोई बड़ा त्योहार, विवाह

समारोह या अन्य महत्वपूर्ण आयोजन तो नहीं है। यदि ऐसा कोई अवसर हो, तो ऐसी तारीखों से परहेज करते हुए वैकल्पिक मतदान तिथि का निर्धारण किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को समय से आगे सोचते हुए कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक मतदाता, चाहे वह देश में हो या विदेश में, अपने माताधिकार का प्रयोग अवश्य करे।

चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी: सिर्फ नागरिकों को ही मिले वोट देने का अधिकार

हाल ही में नियुक्त हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव सुधारों की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने देशभर के 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे वैश्विक लोकतंत्रों की चुनावी प्रणाली और राज्य-स्तरीय चुनाव नियमों का गहन अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन सदन में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई-ऑफिस और डिजिटल फाइल मैनेजमेंट को भी लागू किया गया है - जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सराहनीय प्रयास हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या ये प्रयास मतदाता पहचान की शुद्धता को भी सुनिश्चित कर पाएंगे? आज भारत के कई हिस्सों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध घुसपैठियों को वोटर आईडी जारी किए जा रहे हैं। इनमें से कई लोग न केवल मतदाता बन जाते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक में भी तब्दील हो जाते हैं।

दूसरा सवाल यह है कि इन दोनों चर्चाओं में आया है कि एक ही मतदाता के अलग-अलग जिलों में या शहरों में या राज्यों में कई वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। इन डुप्लीकेट सिस्टम को जितनी शीघ्रता से चुनाव आयोग हटाएगा, उतना ही देश की सुरक्षा और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए फायदेमंद होगा।

पश्चिम बंगाल: जन सांख्यिकीय बदलाव का जीवंत उदाहरण : पश्चिम बंगाल पिछले कुछ दशकों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत-बांग्लादेश सीमा से सटी जमीन पर हजारों लोग बगैर वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हैं और स्थानीय राजनैतिक समर्थन और ढोली प्रशासनिक जांच के कारण आसानी से भारतीय मतदाता बन जाते हैं। यह जनसांख्यिकीय बदलाव न केवल स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संरचना और कानून-व्यवस्था को

प्रभावित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी गहराई से नुकसान पहुंचाता है। कई पूर्व अधिकारियों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल के सीमावर्ती जिलों में कुछ जगहों पर स्थानीय जनसंख्या में गैर-नागरिकों का अनुपात 25-30 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

वोटर आईडी के लिए नागरिकता सत्यापन क्यों है जरूरी?

आज की प्रणाली में नाम, पता और उम्र के आधार पर वोटर आईडी मिल जाता है। कोई ठोस नागरिकता प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या नागरिकता पंजीकरण का सत्यापन अनिवार्य नहीं है। नतीजतन, फर्जी पहचान पत्र बनाकर अवैध घुसपैठिये भी मतदाता बन जाते हैं।

इस घातक खामी को दूर करने के लिए नियम उपाय अत्यंत आवश्यक हैं:

1. सी.पी.एन.और.पुराने.वोटर.आईडी.को.राष्ट्रीय.नागरिक.रजिस्टर.से.जोड़ा.जाए. : जिस तरह असम में प्रक्रिया अपनाई गई, उसे तकनीकी रूप से दुरुस्त कर अब पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

2. आधार, पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र से वोटर आईडी की क्रॉस वेरिफिकेशन: आधार की बायोमेट्रिक जानकारी और पासपोर्ट की राष्ट्रीयता आधारित पुष्टि का उपयोग कर मतदाता पंजीकरण को अधिक सख्त बनाया जाए।

3. डिजिटल जियो-टैग वेरिफिकेशन टीमें का गठन: हर मतदाता के पते का ऑन-ट्राउंड डिजिटल सत्यापन किया जाए, जिससे फर्जी पते पर वोटर आईडी लेना मुश्किल हो।

4. फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सख्त सजा का प्रावधान:

फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी लाभ लेने या वोटर आईडी बनवाने पर कानूनी कार्रवाई हो और तुरंत आईडी निरस्त किया जाए। एक राष्ट्र, एक चुनाव तभी संभव जब एक समान नागरिक पहचान सुनिश्चित हो

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की यह पहल कि पूरे देश में एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए - ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक - एक दूरदर्शी योजना है। लेकिन जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि इस सूची में केवल भारतीय नागरिक शामिल हों, तब तक यह प्रयास अधूरा और भ्रामक होगा। राज्यों के बीच नियमों की असमानता, स्थानीय दबाव, भ्रष्टाचार और तकनीकी कमजोरियाँ

प्रभावित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी गहराई से नुकसान पहुंचाता है। कई पूर्व अधिकारियों और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बंगाल के सीमावर्ती जिलों में कुछ जगहों पर स्थानीय जनसंख्या में गैर-नागरिकों का अनुपात 25-30 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

वोटर आईडी के लिए नागरिकता सत्यापन क्यों है जरूरी?

आज की प्रणाली में नाम, पता और उम्र के आधार पर वोटर आईडी मिल जाता है। कोई ठोस नागरिकता प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या नागरिकता पंजीकरण का सत्यापन अनिवार्य नहीं है। नतीजतन, फर्जी पहचान पत्र बनाकर अवैध घुसपैठिये भी मतदाता बन जाते हैं।

इस घातक खामी को दूर करने के लिए नियम उपाय अत्यंत आवश्यक हैं:

1. सी.पी.एन.और.पुराने.वोटर.आईडी.को.राष्ट्रीय.नागरिक.रजिस्टर.से.जोड़ा.जाए. : जिस तरह असम में प्रक्रिया अपनाई गई, उसे तकनीकी रूप से दुरुस्त कर अब पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

2. आधार, पासपोर्ट और जन्म प्रमाणपत्र से वोटर आईडी की क्रॉस वेरिफिकेशन: आधार की बायोमेट्रिक जानकारी और पासपोर्ट की राष्ट्रीयता आधारित पुष्टि का उपयोग कर मतदाता पंजीकरण को अधिक सख्त बनाया जाए।

3. डिजिटल जियो-टैग वेरिफिकेशन टीमें का गठन: हर मतदाता के पते का ऑन-ट्राउंड डिजिटल सत्यापन किया जाए, जिससे फर्जी पते पर वोटर आईडी लेना मुश्किल हो।

4. फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर सख्त सजा का प्रावधान:

फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी लाभ लेने या वोटर आईडी बनवाने पर कानूनी कार्रवाई हो और तुरंत आईडी निरस्त किया जाए। एक राष्ट्र, एक चुनाव तभी संभव जब एक समान नागरिक पहचान सुनिश्चित हो

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की यह पहल कि पूरे देश में एक समान मतदाता सूची तैयार की जाए - ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक - एक दूरदर्शी योजना है। लेकिन जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं करते कि इस सूची में केवल भारतीय नागरिक शामिल हों, तब तक यह प्रयास अधूरा और भ्रामक होगा। राज्यों के बीच नियमों की असमानता, स्थानीय दबाव, भ्रष्टाचार और तकनीकी कमजोरियाँ

मिलकर इस समस्या को और जटिल बना देते हैं।

निष्कर्ष : राष्ट्र की सुरक्षा और लोकतंत्र की शुचिता के लिए, चुनाव आयोग को नागरिकता सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। भारत के सामने यह अब एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। जब घुसपैठिये मतदाता बनकर सत्ता के समीकरण तय करने लगे, तो यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र का मजकूर बन जाता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के डिजिटल ट्रांजिशन प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं, लेकिन अव्यवहृत है कि इन प्रयासों को मूलभूत पहचान सत्यापन के साथ जोड़ा जाए। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदाता पहचान और नागरिकता जाँच को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखे - क्योंकि बिना सच्चे नागरिकों के, लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। वे लोग जो अनपढ़ हैं या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, वे अक्सर चुनावी दलों और राजनेताओं के प्रभाव में आकर मतदान कर देते हैं। इस प्रकार, समाज के वही लोग-जो कि कम जानकारी रखते हैं-देश और प्रदेश की सत्ता का निर्धारण कर देते हैं, जबकि पढ़ा-लिखा वर्ग केवल तमाशबीन बना रहता है। यह विडंबना है कि जो लोग देश और समाज को सही दिशा दे सकते हैं, वही अक्सर अपने माताधिकार का प्रयोग नहीं करते। वे या तो आत्मस्वस्थ या छुट्टी का लाभ उठाने के लालच में मतदान से दूर रहते हैं। और जब गलत प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तब वही लोग सबसे पहले शिकायत करते हैं। लेकिन वास्तव में, इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं।

इसलिए मेरा देश के प्रत्येक नागरिक से निम्न निवेदन है कि वे अपने माताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यह अधिकार केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपके और आपके देश के साथ ही आपके बच्चों के भविष्य की नींव है। मतदान करते समय किसी के प्रभाव में न आएँ, न ही किसी लालच में-बल्कि अपने विवेक और आत्मचिंतन के आधार पर सही उम्मीदवार को चुनें। एक जागरूक मतदाता ही एक उज्ज्वल भारत का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद,

—सुनील दत्त गोयल, महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जयपुर, राजस्थान

अजमेर डिस्कॉम ने समग्र राजस्व आवश्यकता तैरिफ एवं निवेश योजना पर प्रैजैंटेशन दिया

अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में ऑडियो-विजुअल प्रैजैंटेशन के माध्यम से जानकारी दी

अजमेर, (कासें)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष विद्युत अभियोग 2003 की धारा 62 एवं 64 के अंतर्गत समग्र राजस्व आवश्यकता टैरिफ निर्धारण एवं निवेश योजना की स्वीकृति याचिका प्रस्तुत की गई है। शुक्रवार को टैरिफ निर्धारण को लेकर पंचशील स्थित अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय में ऑडियो-विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को जानकारी दी गई।

अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पी वर्मा ने उपस्थित

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए याचिका के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि याचिका में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ऊर्जा शुल्क (एनर्जी चार्जेंज) में कमी का प्रस्ताव किया गया है, जबकि सीमित रूप में फिक्स्ड चार्जेंज में वृद्धि की मांग की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित परिवर्तन से लगभग 99 प्रतिशत उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें एनर्जी चार्ज में छूट का लाभ मिलेगा।

घरेलू टेरिफ संख्या 9 व अघरेलू टेरिफ 16 से घटाकर 11

■ **उद्योग, कंज्यूमर राइट संगठन के प्रतिनिधि ने भाग लिया आमजन 13 मई तक आपत्तियां व सुझाव दर्ज करा सकेंगे**

किया :- वर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए घरेलू टैरिफ स्लैब की संख्या को 16 से घटाकर 9 तथा अघरेलू टैरिफ स्लैब की संख्या को 15 से घटाकर 11 कर दिया गया है, जिससे

उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की गणना एवं समझना सरल हो सकेगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने के उपरांत उसे आमजन तक पहुंचाया जाना होता है। आमजन द्वारा दिए गए सुझावों पर डिस्कॉम गंभीरता से विचार करेगा। प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में निदेशक तकनीकी मुकेश चंद बाल्दी, मुख्य अभियंता एमएल मीणा, मुख्य अभियंता राजीव वर्मा, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, कंज्यूमर राइट्स संगठनों के प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं सहित अन्य संबंधित

हितधारक एवं अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सभी हितधारकों ने डिस्कॉम की पारदर्शिता एवं उपभोक्ता हित में उठाए गए कदमों की सराहना की।

13 मई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां व सुझाव :-निगम द्वारा प्रस्तुत याचिका की प्रतियां आम नागरिकों के अवलोकन हेतु अजमेर डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालयों, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के कार्यालय तथा निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आमजन अपनी आपत्तियां अथवा सुझाव निर्धारित प्रारूप में 13 मई तक प्रेषित कर सकते हैं।

विकसित और विश्व गुरु भारत बनाने में नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण : राज्यपाल बागड़े

बांसवाड़ा, (निर्सं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षकों का आब्हान किया कि वे शब्द, रूचि, उदाहरण और आचरण को अपना शस्त्र बनाते हुए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करें। इन सूत्रों से ही हम विश्व गुरु बनने का सपना साकार कर सकते हैं। बागड़े गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि शिक्षा बढ़ते पानी की तरह यह जितना बढ़ेगा उतना ही शुद्ध होगा। यदि इसे बांधकर रख दिया गया तो खुद का ज्ञान भी अनुपयोगी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानरूपी शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।

■ **गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ**

लेकिन एक महर्षि ने कहा कि यह सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि आचरण नहीं होगा तो इनका दुरुपयोग ही होगा। बागड़े ने कहा कि हमें मन बनाना होगा और मन को बनाने की विधाओं में नये उदाहरण, नई तकनीक और जज्बा महत्वपूर्ण है।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने पूरे मन, दृष्टि और व्यवहार से विद्यार्थियों को ज्ञान दें क्योंकि एक विद्यार्थी शिक्षक के आचरण को देखकर ही उसी आचरण को अपनाता है। उन्होंने कहा कि चेतना, गुणवत्ता और जवाबदेही के भाव हममें जगाने होंगे। राज्यपाल ने प्रेरित करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद दो शिक्षा नीति अस्तित्व में आई लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में सनातन मूल्यों की स्थापना के साथ-साथ युगीन आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम है। हमारे राज्य की सशक्त

परम्परा रही है जहां ईला न देणी आपणी हालरियो हुलराय द्वारा जहां मैं अपनी कोख से ही देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का पाठ सीखाती है वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारभूत तत्त्व जवाबदेही सभी का उद्देश्य होना चाहिए तभी या भारत, सशक्त भारत और समर्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे।

मुख्य वक्ता और शिक्षा संस्कृति उद्यान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय संस्कृति अकादमी सक्सेना ने कहा कि किसी भी देश की नींव उसकी शिक्षा पद्धति होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीयता से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि आत्म प्रेमोत्पन्न अनुभूति, एकत्व अनुभूति केवल सिद्धांत नहीं अपितु व्यवहार का विषय और परम ध्येय होना चाहिए। अतिथि देवो भव के कारण हमने सदियों से अनेक जातियों और कबीलों को शरण दी भले ही हमने अनेक दुष्परिणाम झेले

लेकिन हमारी अतिथि परम्परा आज भी मूल्य रूप में जीवंत है। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि सर्वोच्च क्रिया पंडित की महत्ता और अध्ययन हम करते नहीं और शोध जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आज उच्च शिक्षा के मानक बदलने की आवश्यकता है हमें हमारी योग्यता, क्षमता और बोध पर संकोच और अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। कबीले आते गए और हिन्दोस्तान बना गया हमारी संस्कृति और धाती की महत्ता और शक्तिमत्ता ही है कि हम अपने सामर्थ्य से देश और समाज की ओगे बढ़ते जा रहे हैं। आज शिक्षा नीति अंतर्गत आवश्यकता है कि विज्ञान, टेक्नोलोजी और डिजिटल क्षेत्र में भी अपने मूल विषयों और मूल्यों को छोड़े बिना भी विकास को प्राप्त हो सकते हैं। उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय की संकल्पना और प्राप्ति रिपोर्ट कुलपति प्रो. केशव सिंह ठाकुर ने प्रस्तुत की।

सत्र में विषय प्रतिपादन न्यास के जयपुर प्राप्त अध्यक्ष प्रो राजीव सक्सेना ने किया।

राज्यपाल ने इस अवसर कैम्पस की गुलाब वाटिका और जनजातीय संग्रहालय का अवलोकन किया और पूर्व में अपने द्वारा रोपे गए पौधे की जानकारी ली। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम किया गया और कार्यक्रमों में औपचारिक रूप से अमूमन किए जा रहे प्लास्टिक प्रयोग को पूरी तरह खत्म किया गया। अतिथि वक्ताक में भी अतिथियों को तुलसी एवं अन्य उपयोगी पौधे प्रदान किये गये। आयोजन सचिव डॉ. राजीव सक्सेना ने प्रस्तावना पेश की एवं आभार कुलसचिव डॉ. अभिषेक गोयल ने मनाई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, उपखंड अधिकारी रजनी माधवाल, पूर्व सांसद कनकलम काठार, पूर्व राज्यमंत्री धनसिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष पू

राष्ट्र निर्माण में पब्लिक सर्वेंट की अहम भूमिका : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान कर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया है कि वे सभी अमृत काल के योद्धा के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान देंगे तथा उ्कृष्ट लोक सेवा के माध्यम से हमेशा राजस्थान का नाम देशभर में रोशन करेंगे। शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष से चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की पहल की है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माने जाने वाली यह परीक्षा पास करके प्रदेश के युवाओं ने अपने माता-पिता के साथ ही क्षेत्र और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के बाद जीवन में बेहतर कार्य करते हुए परिजनों की खुशी के भाव को जीवन में आगे भी बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने ‘कर्ता के आगे हारे करता’ उक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा दृढ़ संकल्प के साथ की गई मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता के बाद भी चयनित युवाओं के जीवन में नए परिश्रम का दौर शुरू होगा। क्योंकि राष्ट्र निर्माण और गरीब



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को उनके निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान के चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान किया।

कल्याण में लोक सेवक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने जीवन में विनम्रता एवं धैर्य को अपनाते हुए आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने का आा न किया।शर्मा ने कहा कि लोक सेवक प्रशासन के कर्णधार हैं तथा लोक सेवा का महत्व हमारे समाज और राष्ट्र के लिए असीमित है। इसलिए लोक

सेवकों का नवाचारी होना महत्वपूर्ण है, ताकि आम लोगों को बेहतर नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने आ न किया कि हमारे प्रदेश की मिट्टी ने हमेशा से वीरों, विद्वानों और कर्मठ लोगों को जन्म दिया है और अब वे सभी भी अपनी सेवा के माध्यम से गौरवमयी मिट्टी की खुशबू को फैलाएं और

कर्मभूमि के साथ ही जन्मभूमि से जुड़े रहे।

समारोह में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिविल सेवा में चयनित प्रतिभाओं के सम्मान की इस पहल से प्रदेश के होनहारों को प्रेरणा मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोकसेवक के रूप में देश और

भगवान परशुरामजी की शोभायात्रा आज

जयपुर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से शनिवार को शाम साढ़े पांच बजे जलेब चौक से गाजेबाजे और लवाजमे के साथ भगवान श्री परशुराम की शोभायात्रा निकाली जाएगी। ब्रह्म पीठाधीश्वर रामरतनदास देवाचार्य, शुक्र संप्रदायाचार्य अलबेली शरण माधुरी एवं अन्य शोभायात्रा का शुभारंभ करेंगे। मुख्य रथ के आगे 2100 महिलाएं एक ही गणवेश में मंगलगान करते हुए शोभायात्रा की भव्यता में चार चांद लगाएंगी। शोभायात्रा में विभिन्न स्वरूपों की जीवंत एवं स्वचालित 21 झांकियां होंगी।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को फैमिली पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन का लाभ देने को कहा है।

न्यायमित्र पूर्वी माधुर ने बताया कि याचिकाकर्ता 63 साल की एकल बुजुर्ग महिला है और मानसिक दिव्यांग है। उसके पिता सचिवालय और मां चिकित्सा विभाग में कार्यरत थीं। दोनों का पूर्व में निधन होने पर वह अपने भाई-भाभी के पास रहने लगीं। वहीं कुछ सालों पहले उसकी भाभी का भी निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने फैमिली पेंशन के लिए पिता के विभाग में आवेदन किया, लेकिन विभाग ने उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पिता ने सरकारी सेवा में रहते हुए कभी भी याचिकाकर्ता को मानसिक दिव्यांगता के बारे में कोई कायिक विभाग ने जुलाई, 2010 को उसे यह पेंशन देने से इनकार कर दिया।

31 जिला संयोजक एवं सह-संयोजक नियुक्त

जयपुर। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान में जन जागरूकता के लिए प्रदेश के 31 जिलों में संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति की है।

अभियान के प्रदेश संयोजक सुनील भार्गव ने बताया कि अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ जन जागरूकता के लिए जिला संयोजकों एवं सह-संयोजकों की नियुक्ति की गई है।

गंधीर चोट आई और भय का माहौल पैदा हो गया। इसी तरह पूर्व में भी यहां घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा मोदी डूंगरी सेटेलाइट अस्पताल में भी बिना जरूरत बिजली जाने पर टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करने की खबर प्रकाशित हुई है। इस तरह की भविष्य में घटनाएं नहीं हो, इसलिए मामले में प्रसंज्ञान लेकर एसएमएस अस्पताल और जिला प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं।

समय आने पर मैं अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूँगा। आशा बैरवा व डॉ. अर्चना शर्मा में प्रत्येक ग्राम से संबंधित विलेज नोडल अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र के संचालक एवं इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के समन्वयक उपस्थित रहेंगे। ऐसे कुषक जो कि योजना की पात्रता रखते है परन्तु योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर पाए है, उनके आवेदन सीएससी केन्द्रों पर सेचुरेशन कैम्पेन के दौरान पूर्ण करवाये जायेंगे।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने दौसा के लालसोट के एक अस्पताल में प्रसूता की मौत पर केस दर्ज होने के बाद डॉ. अर्चना शर्मा के पुति सुनित उपाध्याय की एसएलपी को सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को आदेश जारी कर विधायक गोठवाल के खिलाफ एडीजे कोर्ट लालसोट, दौसा के 9 फरवरी 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने

सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन

जयपुर। भारत सरकार के निर्देश पर पीएम-किसान योजना के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक ग्राम स्तर पर 1 मई से 31 मई तक 30 दिवसीय सेचुरेशन कैम्पेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत योजनान्तर्गत लाभ से वंचित पात्र कुषकों को योजना से जोड़ा जा सकेगा। इन सेचुरेशन कैम्पों में प्रत्येक ग्राम से संबंधित विलेज नोडल अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र के संचालक एवं इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक के समन्वयक उपस्थित रहेंगे। ऐसे कुषक जो कि योजना की पात्रता रखते है परन्तु योजनान्तर्गत आवेदन नहीं कर पाए है, उनके आवेदन सीएससी केन्द्रों पर सेचुरेशन कैम्पेन के दौरान पूर्ण करवाये जायेंगे।

■ मुख्यमंत्री ने युवा-अधिकारियों से विनम्रता व धैर्य को अपनाने तथा जहाँ से जुड़े रहने का किया आह्वान

समाज की सेवा का सौभाग्य चुनिंदा लोगों को ही मिल पाता है। महानिदेशक पुलिस ने कहा कि अपने सेवाकाल में हमेशा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दें और अपनी सफलता में माता-पिता और परिजनों के योगदान को कभी नहीं भूलें।

समारोह में जयपुर निवासी दृष्टिबाधित मनु गर्ग ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए बताया कि उन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में 91वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी इस सफलता का मूल मंत्र अपनी माताजी के संकल्प को बताया। वहीं देशभर में 20वां स्थान हासिल करने वाले जोधपुर निवासी त्रिलोक सिंह ने बताया कि लोक सेवक के रूप में वे भारतीय सेना में सेवा दे चुके अपने पिता द्वारा दी गई प्रेरणा को आगे बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री ने चयनित प्रतिभाओं को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री के साथ चयनित युवाओं का सामूहिक फोटो सेशन भी हुआ। इस अवसर पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे।

दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लोगो और थीम साँन्ग लांच किया

जयपुर। राज्य में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों के तहत उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ‘बाल विवाह मुक्त राजस्थान’ अभियान की शुरुआत की है।

उपमुख्यमंत्री द्वारा अभियान का नया लोगो और थीम साँन्ग भी जारी किया गया है। यह लोगो और साँन्ग लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित

डॉ.अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

है। जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस सदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अर्चना शर्मा के पति सुनित उपाध्याय की एसएलपी को सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में 20 फरवरी को आदेश जारी कर विधायक गोठवाल के खिलाफ एडीजे कोर्ट लालसोट, दौसा के 9 फरवरी 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने

सिविल लाइंस कूच करने के प्रयास में बेनीवाल समर्थकों सहित हिरासत में

जयपुर। एसआई भर्ती निरस्त करने और आरपीएससी भंग करने की मांग को लेकर आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जालपुरा स्थित आवास से समर्थकों के साथ सिविल लाइंस कूच करने का प्रयास

■ बोले, “एस आई भरती रद्द नहीं की, तो एक लाख युवा कूच करेंगे”

किया, लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट के बाहर बैरिकेडिंग पर रोक दिया। इसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। बेनीवाल के समर्थकों ने डोल बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। एक घंटे बाद पुलिस ने बेनीवाल और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया और सांगानेर सदर थाने ले गई।

इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने सिविल लाइंस कूच करने का ऐलान किया है। अगर सरकार ने एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में प्रदेशभर से एक लाख नौजवान जयपुर आएंगे और रैली कर शहर को जाम कर देंगे। उन्होंने कहा, वे एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने, रीट लेवल-1 और आरएएस भर्ती की जांच करवाने की मांग को लेकर युवा

अंता विधायक मीणा को मिली सजा रद्द करने से इनकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक सेवक पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अंता विधायक कंवर मीणा को मिली तीन साल की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कंवरलाल की रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए उन्हें तुरंत निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है। अदालत ने कहा कि यदि अभियुक्त सरेंडर नहीं करता तो निचली अदालत उसके गिरफ्तारी वारंट जारी करे। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश कंवरलाल मीणा की रिवीजन याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक निष्पक्ष लोक सेवक जब प्रतिकूल हालात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा था, तब अभियुक्त ने करीब तीन सौ लोगों की भीड़ को उकसाते हुए रिपोल की मांग करते हुए उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। इस प्रकार के अपराध से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि लोक सेवकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है।

रिवीजन याचिका में कहा गया कि घटना के दो दिन बाद काल्पनिक तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी गई है। निचली अदालत में सभी लोक सेवक पक्षदेही हुए हैं। वहीं उसे राजनीतिक द्वेषता के चलते प्रकरण में फंसाया गया है। इसलिए निचली अदालत के दोषसिद्धी आदेश को रद्द किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकीलविवेक चौधरी व परिवादी के अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि घटना के समय याचिकाकर्ता अपराधिक किस्म का व्यक्ति था और उस पर 15

■ हाईकोर्ट ने तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिये

प्रकरण दर्ज थे। अभियुक्त के भय व आतंक के कारण पुलिसकर्मी व लोक सेवक उसके खिलाफ बयान देने की स्थिति में नहीं थे। यहां तक की पुलिस के मौके पर मौजूद होने के बावजूद रिपोर्ट तक नहीं की गई। वहीं अभियुक्त के स्थानीय इलाके में मौजूद होने के बावजूद तीन साल तक उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया। इससे पुलिस की लाचारी साफ नजर आती है। इसके अलावा तत्कालीन प्रशिक्षु आईपीएस व तहसीलदार ने अभियुक्त के खिलाफ बयान दिए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त विधायक की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है।

मामले के अनुसार अकलेरा के तत्कालीन एसडीओ रामनिवास मेहता ने 5 फरवरी, 2005 को स्थानीय कलेक्टर को पत्र लिखा कि 3 फरवरी को मनोहर थाना के पास गांव के लोक खाताखेडी के उपसरपंच के चुनाव का रिपोल कराने को लेकर रास्ता रोक रहे थे। इस दौरान वह और प्रशिक्षु आईपीएस सहित अन्य स्टाफ समझाइश कर रहा था। इतने में कंवरलाल अपने साथियों के साथ वहां आया और उसके सिर पर रिवाजदार लगाकर दोमिनट में रिपोल की घोषणा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसने विभाग की ओर से कराई गई वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़कर जला दी। घटना के समय दो थानाधिकारी व एक आरपीएस भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। कलेक्टर की ओर से इस पत्र को

एसपी को भेजने के बाद 9 फरवरी को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। वहीं बाद में निचली अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। एसीजेएम, मनोहर थाना ने 2 अप्रैल, 2018 को कंवरलाल को बरी कर दिया। इसके खिलाफ परिवादी और राज्य सरकार की अपील पर एडीजे कोर्ट, अकलेरा ने 14 दिसंबर, 2020 को कंवरलाल को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ पेश रिवीजन पर हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके अलावा गत 17 अप्रैल को अदालत ने सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विधायकी रद्द करने की मांग

जयपुर। विधानसभा में अंता विधानसभा क्षेत्र से विधायक कंवर लाल मीणा को विरुद्ध एडीजे झालावाड़ द्वारा 3 वर्ष कारावास की सजा दिए जाने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सभी पक्षों को यथावत रखा गया है।

राजस्थान प्रेक्ष कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोट्यासरा तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात अंता विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा विधानसभा को सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं

■ बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें

करेगा। इस लॉन्च के साथ, राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हर बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभियान के तहत सतर्क निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और सरकार की त्वरित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप

रांका ने बताया कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 पर जानकारी दें।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य

‘ग्राम सिरोली में विकसित होगी आवासीय योजना’

जयपुर। जयपुर के तहसील सांगानेर के सिरोली गाँव में राजस्थान आवासन मंडल आवासीय योजना विकसित करेगा। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं मण्डल अध्यक्ष श्री वैभव गालरिया ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल राजस्थान सरकार की मंशानुसार आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में सांगानेर के सिरोली में 329.17 हेक्टेयर भूमि पर आवासन मंडल द्वारा आवासीय योजना विकसित की जाएगी।

सिविल लाइंस कूच करने के प्रयास में बेनीवाल समर्थकों सहित हिरासत में



पुलिस ने हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया और सांगानेर सदर थाने ले गई।

सात दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा, एसओजी की जांच में सामने आया है कि 400 से ज्यादा एसआई फर्जी तरीके से चयनित हुए हैं। इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर युवा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार

चुप है। उन्होंने इस पूरे मामले में भाजपा-कांग्रेस पर मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा, कि अपनी सरकार के समय सचिन पायलट ने युवाओं को न्याय दिलाने के लिए पैदल यात्रा निकाली थी, लेकिन अब वे इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीना को लेकर

कहा कि वे मंत्री बनने के बाद युवाओं की आवाज नहीं उठा पा रहे। हनुमान बेनीवाल को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगार और बेनीवाल समर्थक वापस सहीद स्मारक पर इकठ्ठा हुए और धरना जारी रखा।

#COSMOS

Gazing Beyond

Exploring the cosmos, one starry night at a time, how International Astronomy Day brings the universe closer to us all.



Twice a year, the world looks up in unison to celebrate International Astronomy Day, a global tribute to the wonders of the cosmos and humanity's endless curiosity about the universe. This special day, observed on a Saturday between mid-April and mid-May (and again in the fall), is more than just stargazing. It's a celebration of science, exploration, and our collective cosmic journey.

A Starry Beginning

International Astronomy Day was first celebrated in 1973, thanks to Doug Berger, then president of the Astronomical Association of Northern California. His vision was simple yet powerful: bring astronomy to the people. Telescopes were set up in public spaces like



parks and shopping malls, inviting passersby to pause and peek into the vast unknown. Since then, the initiative has grown globally, with amateur astronomers, educational institutions, and science organizations hosting events, workshops, and skywatching sessions.

Why Celebrate Astronomy?

Astronomy isn't just about stars and planets, it's a gateway to understanding our place in the universe. From ancient civilizations that aligned temples with celestial bodies, to modern missions probing the edges of our solar system, astronomy

has always pushed the boundaries of human knowledge. It blends art, science, history, and even philosophy. On International Astronomy Day, people are encouraged to explore this fascinating field regardless of their background or age.

What Happens on Astronomy Day?

All over the world, observatories open their doors for free public visits. Planetariums hold special shows, schools organize space-themed activities, and astronomy clubs invite the public to view celestial wonders through telescopes. From lunar craters and Saturn's rings to far-off

galaxies, the universe becomes a little more accessible. In the digital age, even those in light-polluted cities or cloudy regions can join in. Virtual observatories, livestreams from NASA or ESA, and mobile stargazing apps make it possible to explore the skies from anywhere.

India's Cosmic Connection

India has a rich astronomical heritage, from ancient texts like the Surya Siddhanta to modern marvels like the Indian Space Research Organisation (ISRO). Institutions like the Nehru Planetarium in New Delhi and the IUCAA in

Pune often host public events to mark the occasion. Indian amateur astronomy groups are also highly active, conducting public observation sessions, astrophotography competitions, and educational webinars in regional languages.

Looking Forward

International Astronomy Day reminds us that curiosity has no boundaries. It invites us to look beyond the noise of daily life and into the silence of space, a place that holds endless questions and countless possibilities. Whether you're a budding astronomer or just someone

who enjoys a quiet evening under the stars, this day is your invitation to reconnect with the universe.

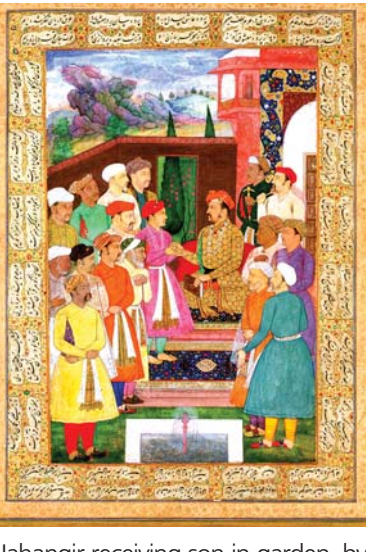
So, this Astronomy Day, step outside, look up, and remember: we're all part of something much bigger, and far more beautiful, than we can ever imagine.

Did Jahangirnama Fall Prey To His Son's Dislike Of Him?

Jahangir's memoirs make it clear that many artists and craftsmen travelled with him, even if their names or activities are rarely mentioned. Therefore, when Jahangir left Agra for the city of Ajmer in Rajasthan in 1613, and remained there for almost three years, signed and dated paintings depicting the emperor must have been done in the city. His son also had his own small entourage of artists accompanying him, even when he undertook military campaigns, as Nanha's depiction of the submission of the redoubtable Rana of Mewar reveals, the artist has included himself at work in the painting.



Jahangir's wine cup, nephrite jade, probably by Said-a-ye- Gilani, 1613.



Jahangir receiving son in garden, by Manohar, 1610-15.



Prince Khurram receiving the submission of the Rana of Mewar in 1614, by Nanha, around 1615-18.



Portrait of Mirza Ghazi, 1610.

been done in the city His son also had his own small entourage of artists accompanying him, even when he undertook military campaigns, as Nanha's depiction of the submission of the redoubtable Rana of Mewar reveals, the artist has included himself at work in the painting.

These prolonged absences from the major cities may explain the apparent reduction in the number of artists in royal service. The



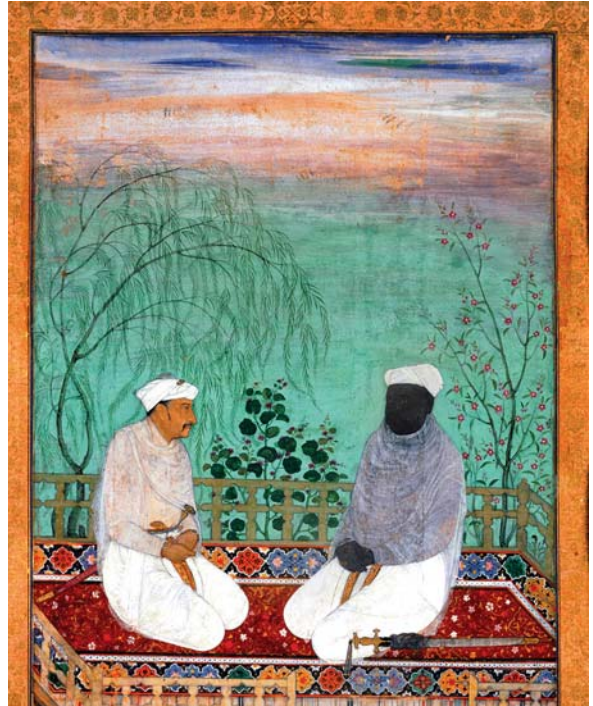
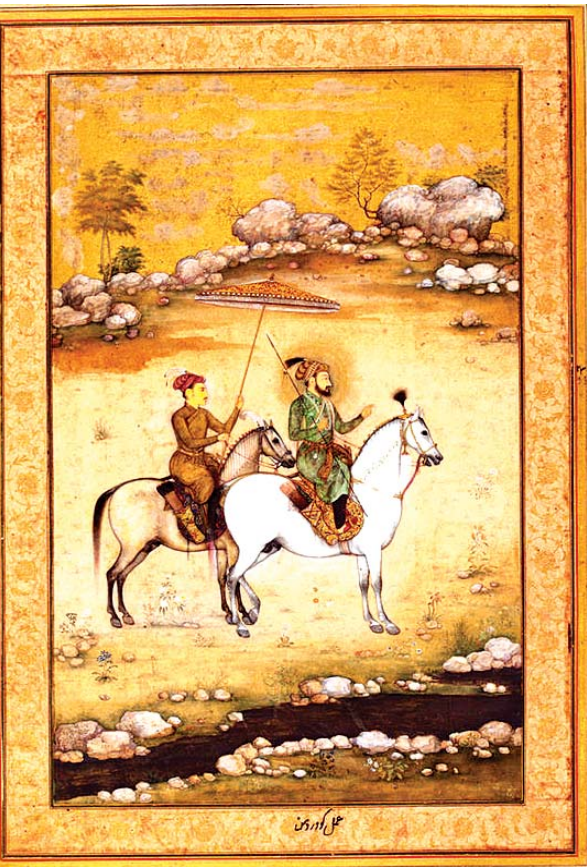
Illuminated calligraphy, by Mir Ali, 1610-20.

House of Books that included the huge imperial library must have remained in the palace at Agra, but the leading artists and calligraphers accompanied Jahangir on his travels. In 1618, when he mentions copies of the Jahangirnama being made, and the artist Abu'l Hasan painting a splendid frontispiece for the royal copy, the court was in Ahmadabad, the capital of Gujarat. This was also the only opportunity that another artist,

PART:3



Left to right- Portrait of Shah Jahan holding an emerald, painting by Mohammad Abed, 1628. Shah Jahan and son Dara.



The Gujarati land-owners Rao Bharah and Jassa Jam, 1680-20.



Portrait of Zain Khan Koka, by Manohar, 1600.

#THE ARTS

begun under Akbar but reached unprecedented levels of accuracy in Jahangir's reign.

Single portraits were clearly used as templates to transfer the image to scenes of court assemblies. A portrait of Mirza Ghazi, with its plain pale green background, is reproduced at exactly the same size in a group scene of Jahangir and his courtiers in a garden.

Different colours have been used to fill in the outline of the group portrait than were used on the single portrait.

The portrait has beautifully painted gold flowering plants on indigo-dyed paper, and decorative borders of great inventiveness were added to paintings and calligraphic specimens that were preserved in the albums of Jahangir, now all dispersed.

Sometimes, the panels of calligraphy often dating to much earlier times and treasured as the work of a great master, were themselves decorated with small panels depicting animals, or with shimmering golden illumination and flowers.

The flowers were derived from European engravings, probably seen by Mughal artists in the borders of Netherlandish prints of Biblical scenes owned by the Jesuits and often brought out by them in court gatherings.

Jahangir mentions in his memoirs an Iranian poet who had been given the title 'Bibadal Khan, the Peerless One'. His name was Sa'ida and he probably arrived at the Mughal court early in Jahangir's

reign. His skills were many and varied. In addition to being a poet, he was a calligrapher, a lapidary (cutter, polisher or engraver of gemstones), and one of several specialists who was able to inscribe in minute lettering the title of Jahangir on his personal possessions made of precious stones, jade or imported Chinese porcelain. He was also a goldsmith who was given the position of head of the goldsmiths department.

His ability to work hardstones perhaps explains the appearance, during Jahangir's reign, of objects made of nephrite jade that were inscribed with the emperor's titles. One of these is a wine cup inscribed with Persian verses, the hijri date 1022, and the regnal year 8 (corresponding to the first half of 1613). The verses can be connected to Sa'ida-ye Gilani, who almost certainly made the cup.

The raw material, imported from Khotan, was probably already in the royal treasury when Jahangir became emperor, but no finished artefacts can be reliably dated before his reign. The techniques used to fashion nephrite jade, which cannot be carved but has to be abraded or incised using diamond drills and small lap wheels, are the same as those used to shape objects of rock crystal, a material commonly found in the subcontinent and already used for hundreds of years.

To be continued...

rajeshsharma1049@gmail.com

#OBITUARY

An Architect of Scientific Thought and Education in India



PROF. S. LOKANATHAN

(1929-2025)

Prof. S. Lokanathan, a distinguished physicist and revered educator, passed away peacefully at his home in Bengaluru on April 30, 2025, at the age of 96.

With 14-year experience of working in US and UK, including a Ph.D. in Columbia with Jack Steinberger (Nobel Laureate 1988), and working in Oxford for 7 years, he joined IIT Delhi in mid 60s. Realizing the need for good teaching in Universities, settled in Rajasthan University in 1969. He retired in 1989, was an emeritus scientist for 5 years, and continued his passion by teaching students in planetarium in Bengaluru since then. He provided an impetus to research in the department of physics through international conferences and

major funding from central governments, setting a research infrastructure with diverse experimental techniques to study materials. He established the High-Energy Physics group which he later led to collaborate with CERN (Centre for European Nuclear Research in Geneva), a collaboration that brought a lot of recognition and funding for Rajasthan University. He coordinated an International program in Physical Sciences benefiting many faculty members in different areas of physics from a post-doctoral training in Sweden. In addition to his well-acclaimed book on Quantum Mechanics, he had major contributions in a program to teach Physics through Experiments. His lifelong commitment to physics and education has left a lasting legacy in both academic and public science communities. Prof. Lokanathan will be deeply missed by his family, colleagues and students who cherish the academic values imbibed from him. He was, in the words of many, "an outstanding professor of physics from the golden age of Rajasthan University." His dedication, humility, and brilliance inspired generations of students, colleagues, and science enthusiasts. Prof. Lokanathan is survived by his family, who, along with the wider academic and scientific community, mourn his loss deeply. His legacy - as a teacher, researcher, and institution builder - will continue to illuminate the path for many in the field of physics.

May his soul rest in peace.

#CANINES

Protect Your Pup

The Essential Vaccination Checklist for Dogs

Just like humans, dogs need timely vaccinations to protect them from serious and often fatal diseases. Whether you're a first-time pet parent or a seasoned dog lover, staying on top of your dog's vaccination schedule is crucial to ensure their long-term health and safety. Here's a handy checklist of core and non-core vaccines that your dog should receive.

Core Vaccines (essential for all dogs)

- Rabies:** Legally mandated in most places, it protects against a deadly virus transmissible to humans.
- Canine Distemper:** A highly contagious virus affecting the respiratory, gastrointestinal, and nervous systems.
- Parvovirus (CPV):** Often fatal in puppies, it causes severe vomiting and diarrhea.
- Adenovirus (CAV-1 & CAV-2):** Protects against infectious hepatitis and kennel cough.

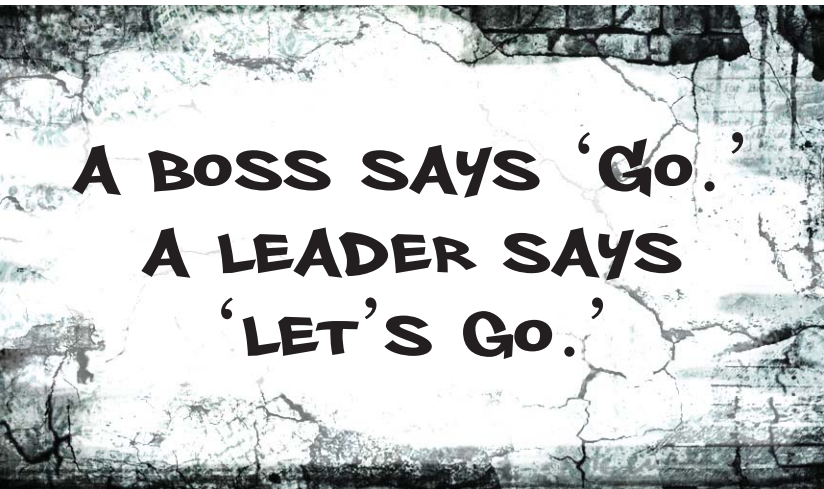
Non-Core Vaccines (based on lifestyle and location)

- Leptospirosis:** Recommended for dogs exposed to standing water or



- wildlife.
 - Bordetella bronchiseptica:** Helps prevent kennel cough, common in boarding or social environments.
 - Lyme disease:** Ideal for dogs in tick-prone areas.
 - Canine Influenza:** For dogs that frequent parks, daycare, or grooming centers.
- Puppy Vaccination Tip:** Begin core vaccines at 6-8 weeks of age and follow up every 3-4 weeks until 16 weeks. Adult dogs need booster shots annually or every three years, depending on the vaccine. Consult your veterinarian to tailor a vaccination plan for your furry friend. A few jabs now can save your dog from serious health risks later. Is your dog up to date with their shots?

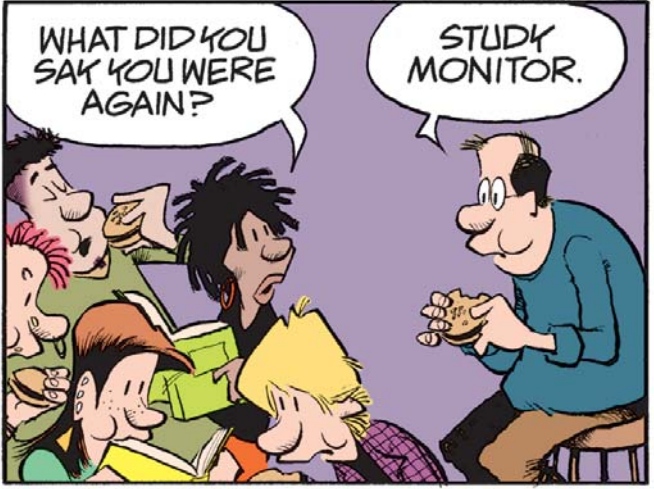
THE WALL



BABY BLUES

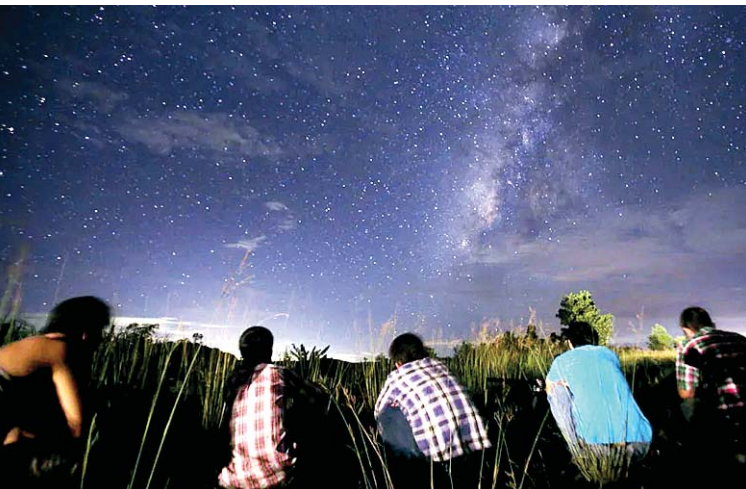


ZITS



By Rick Kirkman & Jerry Scott

By Jerry Scott & Jim Borgman



होटल नाज़ अग्निकांड : एफएसएल व पुलिस टीम ने जांच शुरू की, साक्ष्य जुटाए

चार मृतकों का ज़ेलएन अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया, शव परिजन को सौंपे



होटल में लगी आग की एफएसएल टीम और पुलिस ने जांच की।



होटल में आग लगने सामान जल गया।

अजमेर, (कास)। डिग्री बाजार स्थित होटल नाज में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर शुक्रवार को एफएसएल टीम और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने अग्निकांड में चारों मृतकों के शवों का ज़ेलएन अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिए। मृतकों के परिजन ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार इस दर्दनाक अग्निकांड चार लोगों की जल कर मौत हो गई थी, जबकि चार से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका उपचार ज़ेलएन अस्पताल में जारी है।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य :-क्लॉक टावर थाने के एएसआई राजबीर सिंह ने बताया कि एफएसएल की टीम ने होटल का

निरीक्षण किया और मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। टीम ने जले हुए सामान, वायरिंग और इलेक्ट्रिक उपकरणों की जांच की जिससे यह पता लगाया जा सके कि आग किस वजह से लगी। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस और एफएसएल दोनों ही संभावित कारणों की गहनता से पड़ताल कर रही है।

जांच के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज, बिजली उपकरणों की स्थिति, फायर सेफ्टी इंतजाम और होटल की अनुमति से जुड़ी दस्तावेजी पड़ताल की जा रही है।

होटल में नहीं थे अग्निशमन के पर्याप्त साधन :-क्लॉक टावर थाना पुलिस के अनुसार होटल के मालिक और प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि होटल में अग्निशमन के पर्याप्त साधन थे या नहीं और आग लगने के समय होटल में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए

■ **मृतकों के परिजनों ने रोष जताते हुए होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की**

■ **प्रारंभिक जांच में होटल में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है**

को जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि होटल में अग्निशमन के पर्याप्त साधन थे या नहीं और आग लगने के समय होटल में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए

शिक्षक ने आत्महत्या की

पावटा, (निर्स)। नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत पावटा कस्बा स्थित हीरालाल बाबा के पास एक घर से गुरुवार को प्रागपुरा थाना पुलिस ने कमरे में पंखे में फंदा लगाकर लटके एक शिक्षक का शव बरामद किया है।

प्रागपुरा थाना पुलिस के द्वारा गहन छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उपजिला अस्पताल पावटा भेज दिया गया। साथ ही घटना की सूचना प्रागपुरा थाना पुलिस के द्वारा मृतक के परिजन को भी दी गयी। मृतक की पहचान जौबनेर के छोटी की डूंगरी निवासी विकास मीणा पुत्र भंवर लाल मीणा उम्र 26 साल के रूप में की गयी है। मृतक के संबंध में बताया गया कि वे पावटा उपखंड क्षेत्र के पाथरेडी पंद्राहवात अंतर्गत सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। मकान मालिक परमानंद ने बताया कि करीब दो साल पहले से मृतक को किराये पर कमरा दिया था, जहां से प्रतिदिन अपने समयानुसार विद्यालय जाते थे। घटनास्थल के बगल में रह रहे एक

■ **मृतक की पहचान जौबनेर के छोटी की डूंगरी निवासी विकास मीणा पुत्र भंवर लाल मीणा के रूप में की गयी**

व्यक्ति ने बताया कि उक्त शिक्षक गुरुवार को भी विद्यालय गये थे। विद्यालय से वापस घर आने के बाद परिजनों का फोन रिसीव नहीं करने पर मकान मालिक को शिक्षक को देखने के लिए भेजा।

कमरा बंद रहने पर उक्त गेट में धक्का दिया गया। कोई जबाब नहीं मिलने पर प्रागपुरा थाना पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस की मौजूदगी में गेट को खोला तो शिक्षक का मृत शरीर पंखा में फंदा से लटके हुआ पाया गया। मृतक के डिप्रेशन की बीमारी होने से कोई न कोई परिवार का उसके साथ रहता था। उस दिन भी उसके साथ उसका भांजा था ज्यों कि कोई परीक्षा देने रैनवाल गया हुआ था।

पाली पुलिस लाइन में तीन क्वाटर्स के ताले तोड़े, लाखों की चोरी

चोरी की वारदात के शिकार हुए तीनों पुलिसकर्मी इ्यूटी पर गए हुए थे

पाली, (नि.सं.)। पाली में चोरों ने पुलिस लाइन में ही धावा बोलकर पुलिस को चौका दिया है। चोरों ने यहां तीन पुलिसकर्मियों के क्वाटर्स के ताले तोड़कर वहां से ज्वेलरी और नगदी पार कर ली।

पुलिस लाइन में हुई चोरी की यह वारदात खासा चर्चा कि विषय बनी हुई है। यहां चोरों ने पुलिस लाइन में ही धावा बोल दिया। चोर वहां तीन क्वाटर्स के ताले काटकर और तोड़कर लाखों के गहने तथा नगदी पार कर ले गए। हैरानी की बात यह है कि चोर वारदात को अंजाम देकर निकल गए और कोई जागा तक नहीं। पुलिस वालों को सुबह वारदात का पता चला। पाली पुलिस लाइन में तीन पुलिसकर्मियों के घरों में

हुई चोरी की यह वारदात चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस वालों को सुबह वारदात का पता चला। पुलिस लाइन में चोरी की यह वारदात कास्टेबल अमित कुमार, नरेन्द्र सिंह और एक अन्य कांस्टेबल के घर में हुई।

जानकारी के अनुसार अमित कुमार रात को गश्त में गया हुआ था। नरेंद्र सिंह सुमेरपुर थाने में कार्यरत है। उसकी पत्नी शायी में गई हुई थी। तीसरा कांस्टेबल भी इ्यूटी पर बताया जा रहा है। गुरुवार रात को चोर पुलिस लाइन पहुंचे। बेखोज चोरों ने पुलिस लाइन में स्थित तीन अलग-अलग ब्लॉक में स्थित पुलिसकर्मियों के घरों को निशाना बनाया। इसके लिए चोरों ने बाकादाव इन क्वाटर्स के आजू-बाजू

वाले पुलिसकर्मियों के क्वाटर्स के बाहर से पहले कुंडिया लगा दी ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। उसके बाद चोरों ने कटर से तीनों पुलिसकर्मियों के क्वाटर्स के ताले और कुंडी काटे। चोरों ने तीन पुलिसकर्मियों के घर से नगदी और ज्वेलरी पार की। बाद में आग से वहां से निकल गए। इस दौरान वहां कोई हलचल नहीं हुई। शुक्रवार को सुबह पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को इसका पता चला। सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस वहां पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। वह चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।

युवक ने आत्महत्या की

टोंक, (निर्स)। दूनी थाना क्षेत्र के गांव बंथली स्थित बनाव नदी के पास गुरुवार को एक युवक ने पेड़ से लटक कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जिसकी सूचना पर दूनी व घाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक अजय कुमार (25) पुत्र दुर्गालाल धानका निवासी बंथली के शव को दूनी अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस का कहना है कि गुरुवार शाम को सूचना मिली कि बंथली इलाके में बनास नदी स्थित एक पेड़ पर युवक रस्सी से फंदा बना गले में डाले लटक हुआ मिला है। मौके पर जाकर पुलिस प्रशासन ने शव को पेड़ से नीचे उतारा। मौके पर ही एमओबी व एफएसएल टीम

भी पहुंची, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए। बाद में मृतक युवक के शव को दूनी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए मोचरी में रखवाया तथा परिजनों को सूचना देकर बुलाया। परिजनों ने बताया कि वह ग्रीन हाउस लगाने का काम करता था। उनका कहना है कि उसका किसी से भी झगड़ा नहीं था। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि फाईनेंस कंपनी के लोग अजय को लगातार धमका रहे थे, तीन से सात दिन से उसे परेशान किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर उसने शायद ऐसा कदम उठाया होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनसुधान कायें शुरू किया।

लूणकरणसर का सहनीवाला उन्नत उद्यानिकी तकनीक से मिनी इजरायल बनेगा

बीकानेर, (निर्स)। शासन सचिव कृषि एवं उद्ययानिकी राजन विशाल ने बुधवार को बीकानेर के लुणकरणसर में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्राह्य परीक्षण केन्द्र (एटीसी), आरओसीएल जैतून फार्म और ग्राम सहनीवाला में उन्नत उद्यानिकी तकनीक द्वारा बनाये जा रहे हाई-टेक हार्टिक्लचर मॉडल क्लस्टर का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने कृषि विज्ञान केन्द्र लुणकरनसर का दौरा कर संचालित की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने वार्षिक क्लैण्डर अनुसार विश्वविद्यालय व कृषि उद्ययन विभाग के परस्पर समन्वय से किसानों के लिए प्रभावी प्रशिक्षणों का आयोजन करवाने पर बल दिया, जिससे कृषि विज्ञान केन्द्र का समुचित लाभ क्षेत्र के किसानों के ज्यादा से ज्यादा मिल सके। राजन विशाल ने जैतून फार्म व तेल प्रसंस्करण

उन्होंने लूणकरणसर के ग्राम सहनीवाला का भी दौरा किया, जिसे उद्यान विभाग द्वारा उन्नत उद्यानिकी तकनीकी द्वारा मिनी इजरायल मॉडल

बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा सहनीवाला को हार्टिक्लचर मॉडल क्लूस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसान उन्नत तकनीकी पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, लॉ-टनल, प्लास्टिक मल्ट्र, एकल जल ख़ोत, सामुदायिक जल ख़ोत, सोलर पम्प व ड्रूप संयंत्र में से पॉली हाउस/शेडनेट हाउस के साथ न्यूनतम ख़र्च आयें कोई चार घटक से लाभान्वित किया जा रहा है। चयनित कृषक को पॉली हाउस स्थापना पर दो हजार वर्गमीटर निर्धारित सीमा पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लघु व सीमांत कृषकों को 95 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी, एक करोड़ का सामान जला

आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटों ने पास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया

■ **कस्बे में दमकल नहीं होने से पानी के टैंकर डालकर आग बुझानी पड़ी**

■ **टेंट में ज्यादातर सामान कपड़े का था, आग की लपटें बढ़ती चली गई**

कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

आग की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। लूणकरणसर तहसीलदार विनोद पुनिया व नगरपालिका अधिशासी अधिकारी किशोर चौधरी राहत व बचाव कार्यों की निगरानी में जुटे रहे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली और भीड़ को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई।

भवानी टेंट हाउस के मालिक छगनलाल गोदारा ने बताया कि इस हादसे में गोदाम में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग में स्टील व प्लास्टिक की कुर्सियां, सोफा सेट,

वैलडिंग करते युवक झुलसा

पाली, (नि.सं.)। पाली में एक गाड़ी में वैलडिंग करते समय अचानक डीजल लीक होने से आग लग गई। हादसे में युवक का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जिसका हॉस्पिटल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार सिरोंही जिला निवासी 30 साल के उस्मान पुत्र कालू खान को सुमेरपुर के अनगोर में वैलडिंग शॉप है, जहां वह गुरुवार शाम को एक गाड़ी में वैलडिंग कर रहा था। इस दौरान अचानक डीजल लीक हो गया और आग लग गई। इस हादसे में उसका चेहरा और सीना जल गया। उपचार के लिए सुमेरपुर हॉस्पिटल परिजन ले गए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पाली रेफर किया गया। गुरुवार रात को उसे उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाए जहां उसका उपचार जारी है।

बीकानेर, (निर्स)। बालिका हेजल खत्री की मृत्यु के मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गोंबर और जयपुर के दोनों डॉक्टरों को राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने क्लीन चिट दे दी है। आरएमएसी ने पूरे प्रकरण की जांच की। दोनों पक्षों की सुनवाई की। तीनों डॉक्टरों ने अपना स्पष्टीकरण पेश किया। आरएमएसी ने हेजल की जांच से संबंधित सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद माना कि उसके इलाज में किसी तरह की चिकित्सकीय लापरवाही नहीं बरती गई। जनरल बोर्डी नौ अप्रैल को जयपुर में हुई बैठक में इस प्रकरण से संबंधित फाइल को क्लोज करने का फैसला किया गया।

गौरतलब है कि रानी बाजार निवासी जगदीश चंद्र खत्री की पुत्री

काछोला पंचायत ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

■ **मांडलगढ़ से कार्यमुक्त कर सुवाणा भेजा**

■ **विकास अधिकारी के नोटिस को दरकिनार किया**

मांडलगढ़, (निर्स)। मांडलगढ़ पंचायत समिति का काछोला ग्राम पंचायत में सुवाणा पंचायत समिति से डेपुटेशन पर लगा ग्राम विकास अधिकारी ओम खंडेलवाल रिस्ट्रम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। भूखण्ड पट्टों में फर्जीबाड़े की शिकायत पर मांडलगढ़ बोर्डीओ ने खंडेलवाल को बोते अप्रैल माह में 4 बार नोटिस जारी कर पट्टों का रिकॉर्ड मांगा गया था। लेकिन नहीं दिया गया है। अब खंडेलवाल पर चार्जशीट की तलवार लटकनी नजर आ रही है। वहीं पूर्व में आटुण और हलेड पंचायत में भी आबादी भूमि के भूखण्डों के पुरतैनी पट्टे जारी करने की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा उच्चाधिकारियों की गई थी। जिसमे खंडेलवाल पर पट्टाधारियों से लाखों की राशि वसूलने का आरोप लगाया था। जिसकी जाँच में आरोप पत्र देने के बाद विडिओ ओम खंडेलवाल को सुवाणा विकास अधिकारी ने निलंबित कर दिया है।

ग्राम विकास अधिकारी ओम खंडेलवाल के खिलाफ काछोला पंचायत उप सरपंच देवीलाल माली, सामाजिक कार्यकर्ता ओमनाथ योगी, श्यामलाल

आचार्य ने दो माह पूर्व मांडलगढ़ विकास अधिकारी, जिला परिषद सीईओ ओर कलेक्टर को शिकायत कर काछोला में विगत 6 माह में जारी किए गए एक ही परिवार को भूखण्डों के पट्टों की जाँच की माँग की थी। लेकिन आज तक कोई जाँच शुरू ही नहीं की गई है। इस मामले में विडिओ ओम खंडेलवाल के खिलाफ मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं ग्राम विकास अधिकारी राज विभाग जयपुर और एसबी मुख्यालय जयपुर को शिकायत पत्र भेजा गया है।

पूर्व में अटुण पंचायत में रहे ग्राम विकास अधिकारी ओम खंडेलवाल ने हाइवे सड़क से सटी करोड़ों की भूमि में दो सौ-दो सौ रुपए में पुरतैनी पट्टे जारी करने के मामले को शिकायत के बाद सुवाणा पंचायत समिति विकास

अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर ने विडिओ ओम खंडेलवाल को निलंबित करने का आदेश जारी किया है, और खंडेलवाल का मुख्यालय सुवाणा पंचायत समिति में किया गया है।

मांडलगढ़ पंचायत समिति विकास अधिकारी संगीता व्यास ने बताया कि काछोला ग्राम पंचायत में फर्जीबाड़ा से पट्टे बनाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा मिलते ही जाँच कमेटी का गठन कर 4 अप्रैल 2025 को विडिओ ओम खंडेलवाल को प्रथम नोटिस जारी किया गया और जाँच कमेटी को पट्टों से जुड़ा सम्पूर्ण रिकॉर्ड जाँच कमेटी को सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन रिकॉर्ड नहीं दिया गया।

विडिओ ओम खंडेलवाल को फिर 8,15 व 22 अप्रैल को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। फिर भी सम्पूर्ण रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। अब खंडेलवाल के खिलाफ चार्जशीट जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं सुवाणा बोर्डीओ द्वारा खंडेलवाल को निलंबित करने के तुरंत बाद ओम खंडेलवाल को यहाँ से कार्यमुक्त कर दिया गया है, लेकिन काछोला के पट्टों की जाँच कार्रवाई जारी रहेगी।

छह मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञा पत्र निलंबित

बीकानेर, (निर्स)। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर छह मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। अनुज्ञापत्र प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेन्द्र कुमार केदावत ने बताया कि खाजूवाला स्थित श्री विनायक मेडिकल एंड सर्जिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 9 से 13 मई तक, कक्कू स्थित राधेकृष्ण

पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे

बीकानेर, (निर्स)। राज्य के हाथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने इस वर्ष में भी बुनकरों को नागद पुरस्कार देने प्राश्नधान किया है। जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए जिले की सीमा में कार्यरत हाथकरघा बुनकरों से 16 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि इसके लिए वही बुनकर पात्र होंगे,

जो हाथकरघा पर बुनाई कार्य में पिछले 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। साथ ही जिन्हें गत 3 वर्ष से इस पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया गया है। मंजू नैण गोदारा ने बताया कि पात्र हाथकरघा बुनकर आवेदन (उत्पाद के साथ) 16 जून तक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में कार्यालय समय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आमजन को हीट वेव से राहत देने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे

मुख्यमंत्री भजनलाल ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश दिये

जयपुर, 2 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लू-तापघात (हीट वेव) और गर्मी जनि‍त अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सा विभाग अपनी पूरी तैयारी रखे और जिला कलक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों का पूर्ण रख-रखाव किया जाए एवं किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शर्मा ने कहा कि गर्मी के मौसम में आमजन को बिजली, पानी एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पूरे समर्पण भाव से काम करें, जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए महामारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की तैयारियों को जाएं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में लू से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर अस्पतालों में दवाइयां और उपकरणों की हर समय उपलब्धता हो। हीट वेव की स्थिति में नियमित निगरानी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लू-तापघात और गर्मी जनि‍त अन्य बीमारियों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी रखें।

रखी जाए तथा चिकित्सालयों में हर समय सभी आवश्यक मेडिकल

- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलैक्टर नियमित तौर पर अस्पतालों का निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

संचालित सभी आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों में इस वर्ष तक प्रमुख 12 सेवाएं मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन्हें अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही, एम्बुलेंस की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए। शर्मा ने कहा कि राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से संधारित करने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति की न केवल आभा आईडी बनाई जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आभा आईडी का अधिक से अधिक उपयोग शीघ्र प्रारम्भ हो।

इस दौरान, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने विभाग की योजनाओं , कार्यक्रमों एवं नवाचारों का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर सहित, वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

भाखड़ा बांध से हरियाणा को 8 दिन तक अतिरिक्त पानी मिलेगा

नई दिल्ली, 02 मई। केन्द्र सरकार ने हरियाणा की पानी की जरूरतों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में सलाह दी गई कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) का फैसला लागू किया जाए। इसके तहत, अगले

- केन्द्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में किए गए फैसले के तहत 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिया जाएगा।

आठ दिनों तक भाखड़ा डैम से हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। सरकारी प्रेस विज्ञप्त के मुताबिक, बैठक में यह भी तय हुआ कि डैम भरने के दौरान पंजाब को भी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी दिया जाएगा। इस बैठक में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के प्रतिनिधि और बीबीएमबी के अफसर शामिल हुए।

ये पवित्र अवशेष 02 मई से 21 मई तक वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में वियतनाम में लोगों के दर्शन के लिए विभिन्न पवित्र स्थलों पर रखे जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार रिजिजू ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों की ओर से एक सार्थक संदेश दिया। उन्होंने वियतनाम बौद्ध

भाखड़ा और पोंग डैम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। बीबीएमबी हर साल 21 मई से अगले साल 21 मई तक के लिए इन राज्यों का पानी की कोटा तय करता है।

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर वियतनाम पहुंचे

ये पवित्र अवशेष वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के रुप में 2 मई से 21 मई तक वियतनाम के विभिन्न भागों में प्रदर्शित किए जाएंगे

नयी दिल्ली/ हो चीमिन् सिटी, 02 मई। भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, आंध्र प्रदेश के मंत्री कंदुला दुर्गेश, मिश्रों और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल साथ भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वियतनाम की राजधानी हो ची मिन्ह शहर पहुंचे है।

ये पवित्र अवशेष 02 मई से 21 मई तक वेसाक दिवस स्मरणोत्सव के भाग के रूप में वियतनाम में लोगों के दर्शन के लिए विभिन्न पवित्र स्थलों पर रखे जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार रिजिजू ने इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों की ओर से एक सार्थक संदेश दिया। उन्होंने वियतनाम बौद्ध

विश्वविद्यालय में भारत से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर औपचारिक प्रार्थना के बाद अवशेषों को थान टैम मठ में स्थापित किया गया।

सारनाथ से भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को आज एक विशेष विमान द्वारा हो ची मिन्ह सिटी पहुंचाया गया। इसके साथ ही वियतनाम में 06 से 08 मई तक मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह की तैयारियों का शुभारंभ हो गया है। इन अवशेषों के आगमन पर वियतनाम सरकार और वियतनाम बौद्ध संघ ने आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जो दोनों देशों को एकजुट करने वाले गहन और साझा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। पवित्र अवशेषों को औपचारिक प्रार्थना के बाद थान ताम मठ में श्रद्धापूर्वक स्थापित किया गया।

पवित्र अवशेषों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंच के सहयोग से प्रदर्शित किया जा रहा है। इन्हें 07 मई तक हो ची मिन्ह शहर में जनता के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, उसके बाद 21 मई तक ताई निन्ह, हनोई और हा नाम में प्रदर्शित किया जाएगा।

पवित्र अवशेषों को आज एक भव्य सार्वजनिक शोभा यात्रा के माध्यम से थान ताम पैगोडा लाया गया, जहाँ उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा।

इस उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से तैयार की गई प्रदर्शनी और भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका शामिल है, जो भारत-वियतनाम बौद्ध विरासत की गहरी जड़ों को प्रदर्शित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मामले में अदालती आदेश की पालना के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रकरण में पांच सी टैंडर की जांच की जानी है, जिसमें समय लगने की संभावना है। इसलिए मामले में आठ

सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई आठ सप्ताह के लिए टाल दी है।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने बताया कि साल 2019 में डीओआईटी के तत्कालीन अधिकारी के

खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की ओर से पेश एफआर को एसीबी कोर्ट ने गलत मंजूर किया है। मामले में गत सुनवाई को अदालत ने एसीबी के डीजी रवि हेमराडा की उपस्थिति में डीओआईटी की ओर से बीते पांच साल में दिए सभी टैंडरों की जांच करने के मौखिक आदेश दिए थे।

डॉक्टरों को सिर्फ जैनरिक दवाएं लिखनी चाहिए, कंपनी ब्रांड की नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा होगा तब ही दवा कम्पनियों का भ्रष्टाचार रुकेगा

नई दिल्ली, 02 मई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर अगर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें तो दवा कंपनियों की रिश्तखोरी बंद हो सकती है। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फार्मास्युटिकल मार्केटिंग को समान संहिता पर कानून बनने तक दवा कंपनियों की अनैतिक विपणन प्रथाओं को नियंत्रित करने के दिशा-निर्देश की मांग की गई थी।

मामले में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, दवा कंपनियां अत्यधिक और तर्कहीन दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाती हैं और रिश्तव की पेशकश करती हैं। इस पर अंकुर तभी लगेगा जब डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं ही लिखने का वैधानिक आदेश आएगा।

- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान को एक मिसाल बताया और कहा कि यहाँ कार्याकारी आदेश है कि डॉक्टर्स को जैनरिक दवा ही लिखनी होगी।

पीठ ने कहा, चूंकि मामले में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह इसे अवकाश के बाद सुनवाई के लिए रखेगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि प्रतिवादि्यों ने जवाबी हलफनामा दायर

किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। हालांकि, रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि समिति ने सिफारिश के रूप में क्या सुझाव दिया है।

इस पर जस्टिस मेहता ने पूछा, क्या कोई वैधानिक आदेश है कि डॉक्टरों को सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए, न कि किसी विशिष्ट कंपनी या ब्रांड की दवाओं को। वकील ने जवाब दिया कि कोई वैधानिक जनादेश नहीं है और सिर्फ एक स्वैच्छिक कोड है कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी चाहिए।

जस्टिस मेहता ने कहा, राजस्थान में, एक कार्यकारी निर्देश है कि प्रत्येक मेडिकल पेशेवर को जेनेरिक दवा लिखनी होगी। इसे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी नए उप वायु सेना प्रमुख

नई दिल्ली, 02 मई। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने शुक्रवार को नए उप वायु सेना प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एयर मार्शल एस.पी. धरकर का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। कार्यभार संभालने से पहले एयर मार्शल तिवारी गांधीनगर स्थित दक्षिण-

- उन्हें 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल एस.पी. धारकर की जगह नियुक्त किया गया है।

पश्चिमी वायु कमान (एसडब्ल्यूएसी) के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में तैनात थे। वायु सेना मुख्यालय 'वायु पवन' में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

भारतीय वायु सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने 2 मई 2025 को उप वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है।

पाक अधिकृत कश्मीर के 1000 मदरसे बंद

समझा जाता है कि भारतीय सेना के हमले की आशंका में यह कदम उठाया गया है

- इसी बीच पाकिस्तान ने भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर खोलने की घोषणा की।

इस्लामाबाद, 02 मई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 1000 से अधिक मदरसे कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को यह घोषणा की। विश्वसनीय स्रोतों ने बताया कि भारत की तरफ से हमले के डर की वजह से पीओके में स्थित मदरसों को बंद कर दिया गया। भारत यह दावा करता रहा है कि इन संस्थानों का इस्तेमाल आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के रूप में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि भारत पाकिस्तान के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ पीओके क्षेत्रों में कुछ हमले जरूर करेगा। 29 सितंबर 2016 को, भारतीय सेना के कर्मांडो की टीमों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में प्रवेश कर आतंकी ठिकानों में

छिपे बैठे आतंकवादियों को खत्म किया था। यह कार्रवाई 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी में भारतीय सेना की एक चौकी पर हमला करने के दस दिन बाद हुई थी। हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सरकार के निर्देशानुसार 1000 से अधिक मदरसे बंद कर दिए गए हैं। उन्हें कम से कम 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और छात्रों के लिए छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को गिलगित

और स्कार्डू के लिए सभी घरेलू उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। विदेशी उड़ानों को भी कड़ी निगरानी शुरू की गई। जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) की सभी आने वाले विदेशी विमानों की जांच करने का निर्देश दिया गया। इस बीच पाकिस्तान ने भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों के लिए वाघा सीमा को खुला रखने की घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए थे। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, "हलांकि भारत से पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी, लेकिन यदि भारतीय अधिकारी उन्हें अपनी ओर से सीमा पार करने की अनुमति देते हैं तो लाहौर में वाघा बॉर्डर हमारे नागरिकों के लिए खुला रहेगा।

नैशनल हैरल्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अखबार नेशनल हैरल्ड, उसके सहयोगी पत्र-पत्रिकाओं और उसकी संपत्तियों की स्वामी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड (एजेएल) का यंग इंडियन ड्राइव लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहण किये जाने में कथित धांधली पर आधारित है। इस सौदे से कुछ समय पूर्व वाईआईएल का गठन किया गया था जिसकी अधिकांश हिस्सेदारी कांग्रेस के दोनो शीर्ष नेताओं राहुल व सोनिया के पास है। ईंडी 2014 से इस मामले की जांच कर रही है। यह मामला पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को शिकायत के बाद प्रकाश में आया।

राज्य सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया है।

राज्य सरकार व चुनाव आयोग की ओर से लगातार अदालती निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि उन्होंने जवाब पेश कर दिया है। इसमें कहा है कि पंचायत पुनर्गठन एवं परिसीमन के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। वही, अदालत ने नगर पालिकाओं के चुनाव मामले में भी नोटिस जारी किए हैं। इसलिए यह मामला भी नगर पालिका चुनाव मामले में दायर याचिका के साथ ही सूचीबद्ध किया जाए।

राज्य सरकार के इस जवाब पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साल 2022 में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार व चुनाव आयोग, पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन के कारण पंचायत चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते।

समय पर चुनाव कराया जाना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है। नगर पालिका चुनाव का मामला अलग और नया है, जबकि पंचायत चुनाव वाले मामले में अदालत राज्य सरकार व चुनाव आयोग से चुनाव कार्यक्रम मांग चुकी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने चुनाव आयोग से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 30 मई को तय की है।